भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1440
उत्तर देने की तारीख 04 दिसम्बर, 2024

5जी नेटवर्क शुरू करना

1440. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः
एडवोकेट अदूर प्रकाशः
डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानीः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संपूर्ण भारत में नवंबर 2024 तक कवर किए गए शहरों और जिलों की राज्य-वार संख्या के साथ-साथ देश में विशेष रूप से राजस्थान में कवर किए गए जिलों और शहरों के नाम सहित 5जी नेटवर्क रोलआउट की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए विशेष रूप से 5जी पहुंच में असमानताओं को दूर करने के लिए किए गए उपाय क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा 5जी सेवाओं तक सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल की गई है;

(घ) तटीय बस्तियों में 5जी संयोजकता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित पहल क्या है;

(ङ) सरकार की बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आर्थिक विकास, डिजिटल साक्षरता और प्रौद्योगिकी संबंधी नवाचार और 5जी परिदान के प्रभाव की निगरानी के लिए विद्यमान रणनीतियां क्या हैं;

(च) पिछले पांच वर्षों में बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 4जी और 5जी नेटवर्क से युक्त किए गए गांव और इस संपर्क के लिए शेष गांवों की संख्या कितनी है; और

(छ) क्या सरकार का विचार शेष गांवों को 4जी और 5जी नेटवर्क से युक्त करने का है और यदि हां, तो इन्हें कब तक यह संपर्क प्रदान किये जाने की संभावना है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) राजस्थान के सभी जिलों में 5जी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा, देश भर के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5जी नेटवर्क शुरू किए गए हैं और वर्तमान में देश के 783 जिलों में से 779 जिलों में 5जी सेवाएं उपलब्ध हैं। दिनांक 31 अक्टूबर 2024 तक, देश में 4.6 लाख से अधिक 5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) संस्थापित किए जा चुके हैं जिनमें राजस्थान के 27,508 बीटीएस शामिल हैं।

(ख) से (ङ) सरकार ने 5जी सेवाओं के प्रसार के लिए कई पहल की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. नीलामी के माध्यम से मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम का आवंटन।

ii. वित्तीय सुधारों के परिणामस्वरूप समायोजित सकल राजस्व (एजीआर), बैंक गारंटी (बीजी), ब्याज दरों और जुर्माना युक्तिसंगत हो गए है।

iii. स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम शेयरिंग, व्यापार और सरेंडर की अनुमति दी गई है।

iv. एसएसीएफए (रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति) क्लीयरेंस की प्रक्रिया का सरलीकरण।

v. दूरसंचार (मार्ग का अधिकार) नियमों की अधिसूचना और पीएम गतिशक्ति संचार पोर्टल लॉन्च करने से आरओडब्ल्यू अनुमतियां को सुव्यवस्थित बनाया गया है और दूरसंचार अवसंरचना की संस्थापना के लिए क्लीयरेंस प्रक्रिया में तेजी आई है।

vi. स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की संस्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग के लिए समयबद्ध अनुमति के लिए आरओडब्ल्यू नियमों में प्रावधान किया गया है।

डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा चल रही परियोजनाओं के साथ-साथ इन उपायों से डिजिटल कनेक्टिविटी गैप और कम होने की उम्मीद है।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने तटीय क्षेत्रों सहित पूरे देश में 5जी सेवाओं का विस्तार किया है और स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रण सूचना (एनआईए) में निर्धारित न्यूनतम

रोलआउट दायित्वों से बढ़कर इसका विस्तार किया है। इन दायित्वों से परे मोबाइल सेवाओं का विस्तार करना दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की तकनीकी-वाणिज्यिक प्रतिफलों पर निर्भर करता है।

4जी और 5जी नेटवर्क की उपलब्धता से प्रयोक्ताओं के मध्य ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा के साथ-साथ ऑनलाइन सरकारी सेवाओं के प्रयोग को अपनाये जाने में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में 100 संस्थाओं में 5जी प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा रही हैं। इससे नई दूरसंचार तकनीकों के लिए दक्षता विकसित करने में मदद मिलेगी और राष्ट्रीय एवं वैश्विक आवश्यकताओं के लिए यूज केस विकसित करने के लिए स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों को शामिल किया जाएगा। इनमें से चार 5G प्रयोगशालाएँ राजस्थान में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर और एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्थापित की गई हैं।

(च) और (छ) दिनांक 31 अक्टूबर 2024 तक बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुल 3285 गांवों को पहले ही 4जी तकनीक से कवर किया जा चुका है।

भारत सरकार ने '4जी सेचुरेशन परियोजना' शुरू की है जिसका उद्देश्य देश के सेवा से वंचित सभी गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करना है। 26,316 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से ऐसे 24,680 गांवों को कवर किया जाएगा। इस परियोजना के तहत, बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 4जी कवरेज के लिए 214 गांवों की पहचान की गई है। इसके अलावा, दूरसंचार सेवा प्रदाता भी अपने मोबाइल नेटवर्क का लगातार विस्तार कर रहे हैं।

******